लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2861

10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

समर्थ 2.0 के अंतर्गत महिलाओं का रोजगार

2861. डॉ. विनोद कुमार बिंद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बढ़ती लागत और कारीगरों की घटती आय को देखते हुए हथकरघा और हस्तशिल्प श्रमिकों के लिए वित्तीय और विपणन सहायता को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प कामगारों को सहायता प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और हथकरघा क्षेत्र में कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएसएस) जिसके तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों और कामगारों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघों और सहायक उपकरणों, सौर प्रकाश व्यवस्था, वर्कशेड निर्माण, उत्पाद विविधीकरण, सामान्य अवसंरचना, इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी), हैंडलूम मार्क (एचएलएम) और जीआई टैग के माध्यम से ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स, घरेलू और विदेशी विपणन, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) हस्तशिल्प क्षेत्र में राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम का विपणन सहायता और सेवाएं (एमएसएस) घटक जिसके तहत कारीगरों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय सहायता में स्थान का किराया, प्रचार, अवसंरचना और टीए/डीए/भाड़ा शुल्क शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 8.81 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ कुल 72 एमएसएस कार्यक्रम, 01 अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम (आरबीएसएम, मुरादाबाद) और 72 सीडीएपी कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं।

***